are the measures to be taken is a matter of detail Perhaps the hon Member may have to put a separate question

Mr Speaker: Shri Prakash Vir Shastri.

Shri Prakash Vir Shastri: Question No 1354

Shri Jagannath Rao Joshi: The other question on sugar may also be taken up along with this

Mr. Speaker. There may be a dozen questions on sugar, but it does not mean that they should be attached to this question

चीनी की मिलों का बन्द होना

+

*1354 श्री प्रकाशवीर शास्त्री
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री ·

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या चीनी की मिलों को पर्याप्त मात्रा में गन्ना उपलब्ध न होने के कारण कुछ चीनी मिलो के आगामी वर्ष मे भी बन्द रहने की सभावना है,

(ख) यदि हा, तो इसके परिणाम-स्वरूप अनुमानत कितने श्रमिक बेरोजगार हो जायेंगे, और

(ग) चीनी की अत्यधिक कमी को दृष्टि में रखते हुए सरकार का इस सबध मे क्या कार्यवाही करने का विचार है?

खाद्य कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय मे राज्य-मंत्री (श्री अण्णा साहिब शिन्दे) (क) और (ख) चीनी कारखानो का चलना अथवा बद होना उनके पास पेरने के लिये गन्ने की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इस अवस्था में अगले मौसम के लिये इस सबध में अभी कोई पक्का अनुमान नही लगाया जा सकता है। तथापि राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार मध्य प्रदेश में सभी पाच चीनी कारखानें और महाराष्ट्र मे एक कारखाना काम नही करेगा और दक्षिण बिहार मे चार चीनी करखाने और उत्तरी बिहार में पाच चीनी कारखाने अगले मौसम में काम न करने की सोच रहे हैं। यदि सभी उल्लिखित कारखाने बन्द रहते हैं तो उससे अनुमानत 11,000 कर्मचारियो पर प्रभाव पड सकता है।

(ग) 1967-68 में अधिक से अधिक चीनी का उत्पादन करने के उपायो पर राज्य सरकारो के परामर्श से विचार हो रहा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री · मंत्री महोदय ने अभी कुछ राज्यो में चीनी मिलो का काम बन्द रहने के विषय मे जानकारी दी है। क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश मे भी लगभग तीस छोटी मिलो के बन्द होने की सभावना है और क्या उन मिल मालिको ने केंद्रीय सरकार को रिप्रेजेन्टेशन दे कर यह सुझाव दिया है कि गन्ने की कीमत घटा दी जाय और चीनी पर से कन्ट्रोल हटा दिया जाये यदि हा, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

Shri Annasahib Shinde: We contacted the Uttar Pradesh Government and the Uttar Pradesh Government has communicated to us that though the duration of work in factories as a result of less availability of cane might be less, no factory is likely to be closed That is the information supplied by the Uttar Pradesh Government But some factories have brought to our notice that there is likely to be considerable difficulty in the availability of cane in the coming season and they are afraid of a closure The Uttar Pradesh Government has also indicated to us that there has been a steep fall in cane acreages, from 25

lakh acres to 20 lakh acres last year and to 15 lakh acres this year.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह प्रश्न पूछा है कि जो मिलें बन्द होने जा रही है क्या उन्होंने यह सुझाव दिया है कि गन्ने की कीमत को बढ़ा दिया जाये और चीनी पर से कंट्रोल को हटा दिया जाये; यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

Shri Annasahib Shinde: All these suggestions have been received by the Government and all these matters are under active consideration.

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस सदन में जब भी गन्ने की कीमत बढ़ाने के सम्बन्ध में प्रश्न आता है, जिसके कारण चीनी का उत्पादन बराबर गिरता जा रहा है, तो सरकार बार-बार यह उत्तर देती है कि इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है । सब राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कह रही हैं ।

Mr. Speaker: The Food Minister has said that he will make a statement and take a decision in 10 to 15 days Wait for 10 to 15 days

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : इस सरकार के जो पद्रह दिन हैं, क्या वे पद्रह साल या पद्रह महीनों के बराबर है ? इस बारे में कब तक घोषणा होगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री जगजीवन राम) : यह पद्रह साल और पद्रह महीने का प्रश्न नहीं है । सदन को मालूम होना चाहिए कि गन्ना लगाने का मौसम बीत चुका है । इसलिए अगर आज गन्ने का दाम जाहिर कर दिया जाये, तो उसका गन्ने के उत्पादन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है । गन्ना की खेती लगाई जा चुकी है ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अगर गन्ना खडसारी को जाने लगा और मिलों को न मिला, तो उस पर असर पड़ेगा ।

श्री जगजीवन राम : क्रशिंग सीजन नवम्बर में शुरू होता है ।

मैंने पहले ही बताया था कि चीनी के सम्बन्ध में पूरी नीति विचाराधीन है और इसीलिए गन्ने के मूल्य को दोबारा बढाने की घोषणा नहीं की जा सकी ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री वह घोषणा कब तक की जायेगी ?

श्री जगजीवन राम : वह बहुत शीघ्र ही की जायेगी । गन्ने की कीमत के सम्बन्ध में मैंने कहा था कि उस पर पुनर्विचार करके इसको कुछ बढाने का ही खयाल है । वह ऐसे समय पर कर दिया जायेगा जिससे अगले गन्ने की पिराई पर उसका असर पड सके ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : गत वर्ष चीनी की मिलों को गन्ना न मिलने से जो मजदूर बेकार रहे क्या उनके आकडे भी केन्द्रीय सरकार के पास है, यदि हां तो मैं जानना चाहता हू कि कितने मजदूर बेकार रहे और कितनी आर्थिक हानि उनको उठानी पड़ी ?

Shri Annasahib Shinde: We will try to collect the information from the State Governments. Unfortunately, the State Governments also do not have exact information about this. Many of the factories in West U.P., North Bihar, Orissa, M.P. and Kerala have had a very short duration and this must have affected the employment potential

श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को यह सुझाव भेजा है कि हमारे यहां कुछ ऐसी चीनी मिलें है जिनकी वित्तीय दशा को सुधारने के लिए एक कारपोरेशन बनाई

जाए और उनको चलाने के लिए उन्हें कुछ सहायता दी जाए और साथ ही यह कहा है कि चीनी को भी डिकंट्रोल किया जाये ?

Shri Annasahib Shinde. Many suggestions are there about the modernisation of outmoded mills A committee under the chairmanship of Dr Kurien went into this problem and made a number of suggestions We are awaiting the comments of the State Governments about the recommendations About other things, the Minister has already replied

Shri Shivajirao S Deshmukh In the past it has been the sad experience of the House that whenever any decision which is unpalatable to the treasury benches is forced upon them by the Chief Ministers conference or any other forum it has been forestalled under the plea of being under consideration And one fine morning it is announced that the decision is otherwise In the background of this very sad experience may I take it that the Government are really considering decontrol of sugar? The existing practice of breaking up the northern states into one sugar zone for every factory and in the southern states into one sugar zone for one state has resulted in the number of sugar zones being at least four times the number of States in the Union Does Government propose to do anything to streamline or rationalise the sugar zones so that the tragedy of closure of sugar mills is not repeated?

Shri Annasahib Shinde I do not know what the hon Member means by saying that all of a sudden we take a decision We are a federal country and we have to consult the States

Shri Jyotirmoy Basu Are you de controlling sugar or not?

Shri Annasahib Shinde How can we say that when the whole matter is under consideration?

Shri Shivajirao S. Deshmukh: My question has not been answered. Do Government really contemplate decontrol of sugar, as recommended by all the Chief Ministers? If the answer is 'no', will there be a rational distribution of zones?

Shri Jagjivan Ram I have already said that the entire sugar policy is under consideration of Government Beyond that I am not prepared to disclose anything

श्री रवी राय मंत्री महोदय ने कहा है कि वह राज्य सरकारों के साथ सलाह मश्विरा कर रहे हैं । इस सिलसिले में मैं उनका ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि बिहार के खाद्य मंत्री श्री कपिल देव सिंह को केन्द्रीय सरकार के खिलाफ यह शिकायत है कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार को पूछती नहीं है और गन्ने की कीमत बढ़ाने के सिलसिले में जो राज्य सरकार सोचती है उसके बारे में कोई कदम नहीं उठाती है यह क्या सही है ?

श्री जगजीवन राम कपिल देव सिंह जी को बहुत शिकायतें हो सकती हैं क्योंकि बिहार में जो गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए शूगर केन [सैस रखा गया है उसमें से इस काम के लिये बहुत खर्च नहीं किया गया और बिहार में गन्ना उद्योग बहुत बुरी अवस्था में है । लेकिन जो इस सम्बन्ध में खत गया है वह सभी स्टेट गवनमेंट्स को गया है और यह खत बिहार भी गया है और अगर उन्होंने ऐसा कहा है कि मेरे पास नहीं आया तो मैं कह सकता हूं

श्री रवी राय अखबारों में यह आया है ।

श्री जगजीवन राम अखबारों में दुनिया भर के बयान निकलते हैं । हमारे पास कुछ भी नहीं आया है । अखबारों में जो बयान निकलते हैं उनका मैं नोटिस नहीं लेता हूं । मैं सदन को इतना ही बता देना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों को

केन्द्रीय सरकार ने पत्र लिखा है और बिहार सहकार को भी लिखा है।

श्री विभूति मिश्र : क्या यह सही है कि जिस अनुपात से गल्ले का दाम बढ़ा है उस अनुपात से गन्ने का दाम नहीं बढ़ा है ? क्या यही कारण नहीं है कि पिछले साल और इस साल भी गन्ने की खेती कम होने जा रही है ? क्या यह भी सच नहीं है कि गन्ने के उत्पादन को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सरकार सैंट्रल एक्साइज लेती है और स्टेट सरकार केन सैस लेती है और कोई भी दोनों में से इस राशि को उत्पादन बढ़ाने पर खर्च नहीं करता है ?

Shri Annasahib Shinde Sir during the last two years the prices of food-grains have slightly gone up and that is having an effect on the sugarcane price This matter is engaging the attention of Government That is why, as has been mentioned by the hon Minister all these matters whether the sugarcane price is to be increased and if so to what extent the increase should be given etc, are under active consideration About cane cess also I entirely agree with the hon Member We desire the State Governments to utilise the amount of cane cess for the development of cane so that cane development is not adversely affected

Shri Nath Pai Sir I believe we should be in the world sugar market we should be earning an amount of foreign exchange and Government has to export a certain amount of sugar to some foreign countries I want to know what is the loss we are incurring by this transaction, and may I know whether in view of this year's very low production and anticipated further decline in production this policy of exporting will continue?

Shri Annasahib Shinde: I have already mentioned in the House that we do not want to export any more Whatever was exported last year was as a result of previous commitments with foreign governments About future commitments etc., we will have to take a decision But our attitude towards this problem is that since the availability in the country is less we will have to look to our needs first and then see whether we can export or not

Shri Nath Pai. Sir, did you hear my question or not? This was only part of my question The other part was what was the loss incurred by this export He gave a satisfactory reply that they are going to stop further exports What has been the loss in the past, may I know?

Shri Annasahib Shinde: I will require notice for this

Mr. Speaker: That is exactly what I thought

श्री शिव नारायण : अध्यक्ष महोदय, मैं गांव का रहने वाला हूं। मैं गन्ना बोता हूं (इंटरप्शन) मैं इनकी तरह से नहीं हूं जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं। मैं किसान हूं, गन्ना बोता हूं। मैं सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या कारण है कि आप इंतजाम नहीं कर सकते हैं और ठीक दाम गन्ने का किसान को नहीं दे सकते है। ब्लैक मार्किट इस मुल्क में पनप रही है। चीनी आज चार रुपये और छ रुपये सेर ब्लैक मार्किट में बिक रही है। एक मन गन्ने में पौने चार सेर चीनी आती है। चार सेर चीनी का दाम चौदह सोलह रुपये होता है। हमें आप पौने दो रुपये मन के हिसाब से देते है। उस में से आठ आना गाडा का किराया हम देना पड़ता है। मैं समझता हूं कि सरकार अगर ठीक इंतजाम नहीं कर सकती है तो क्यों नहीं हम को और मिल मालिकों को अकेले छोड़ देती है और हम दोनों आपस में निपट लेंगे ? इस बारे में सरकार का क्या विचार है ?

Shri Annasahib Shinde: The hon Member knows that sugar is a controlled commodity Sugarcane price and sugar price are controlled under the Essential Commodities Act Thereby I do not mean that some quantities do not slip away into the blackmarket But the substantial portion is provided through ration shops and card distribution

Shri D. N Patodia The price of sugarcane is controlled only so far as cane supplied to sugar factories concerned but not so far as khandsari and gur are concerned In addition extraction percentage when cane is supplied to sugar factories is as high as 90 per cent whereas it is only about 60 per cent if it is given for khandsari Therefore the present policy is directly resulting in the lower total production of sugar, khandsari and gur *(Interruptions)*

Shri D N Patodia In view of that, may I know whether it is a fact that on account of diversion of sugarcane to khandsari there is decreased production of sugar within the same availability of cane and, if that is so may I know what prevents the Government today from controlling the entire sector all the three sugar khandsari and gur, for de controlling the entire sector?

Shri Annasahib Shinde It is true that as a result of the imbalance that has developed in the prices of khandsari jaggery and sugar considerable quantities of sugarcane are diverted to manufacture of khandsari and jaggery and as a result sugar factories have suffered because of less availability of sugarcane But the hon Member will appreciate that jaggery and khandsari manufacture is a big decentralised sector spread all over the country To control this sector spread all over the country is a difficult proposition Regarding the other part of the hon Member s question about de-control the hon Minister has already replied to it

Shri D N. Patodia: One point has not been replied to, whether such diversion has resulted in a direct cut in the production of sugar on account of low extraction.

Shri Annasahib Shinde: I have mentioned that Sugar production has been less this year on account of diversion of sugarcane to khandsari

श्री सीता राम केसरी : क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो शुगर फैक्ट्रियां बिहार में बेकार होती जा रही हैं उन शुगर फैक्ट्रियों को मैसूर या आन्ध्र में ले जाने की बात है कि जिस में वह चलें ?

Shri Annasahib Shinde I do not think we have any such proposal either before us or before the State Governments

Shri S M Banerjee I would like to know from the hon Minister whether he is aware that Kanpur is the biggest sugar market and

Shri Surendranath Dwivedy And the biggest blackmarket

Shri S M Banerjee whether it is a fact that despite all the rigid measures sought to be taken by this government sugar is being sold in every place at Rs 4 or Rs 4 50 per kilo and in Bombay it is practically being sold at Rs 6? If so I would like to know what positive steps have been taken by Government whether they have issued any directions to the State Governments to see that the sugar price remains at Rs 2 or 1 50 or something near that because sugar has become the rarest commodity available which people cannot purchase?

Shri Jagjivan Ram: The allotments from the factories are made to the various State Governments So far as distribution in the State is concerned it is the responsibility of the State Government.

Shri S. M. Banerjee: What is happening in Delhi

Shri Jagjivan Ram: I am coming to that I see no reason why the State Governments cannot make arrangements that, by and large, sugar is sold at the price at which it is to be sold and people receive that, even though a reduced quantum

श्री कंवर लाल गुप्त सवाल यह है कि दिल्ली में यह क्या कर रहे हैं ? दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नोर करके सीधा भी लोगों को दे रहा है।

Shri Jagjivan Ram In Delhi there is complete rationing and people are getting it

Shri Kanwar Lal Gupta: He should reply properly to the questions asked

Shri Biswanath Roy In view of the fact that the acreage under sugar cane cultivation has decreased considerably and consequently the production of sugar in the next season would be much less how is the government going to meet the internal demand of sugar?

Shri Annasahib Shinde: Measures for encouraging increased cultivation of cane, to enable factories to have adequate availability of cane all these matters are under consideration

Shri V. Krishnamoorthi Neither de control of sugar nor abnormal rise in the cane price will solve the problem, because it will be at the cost of the consumer at last Even now the State Governments are issuing licences for the opening of khandsari mills The Sugar Mills Association is stressing that licences for khandsari mills should not be given If a ban is put on the giving of licences for new khandsari factories and also on sending cane to khandsari mills, the problem can be solved Will the Government consider the putting of this ban temporarily in order to solve this problem?

Shri Annasahib Shinde: I wish the problem were so simple as the hon Member is mentioning But may I submit for his kind consideration that our general policy has been, as far as the factory areas are concerned from which the factories are fed, that State Governments should not allow the putting of khandsari plants

Shri Gadilingana Gowd In view of the shortage of sugar in the country has the Government any proposal to encourage co-operative marketing societies to instal khandsari sugar factories in areas not covered by sugar factories which only cost Rs 3½ lakhs?

Shri Annasahib Shinde The State Governments can encourage that activity

श्री भा० दा० देशमुख : अभी मंत्री महोदय ने कहा है कि इसके परिणाम के कारण कई फैक्ट्रीज बन्द होने वाली हैं। मैं समझता हूं कि लगभग 7 लाख टन प्रोडक्शन उसमें घट जायगा। तो ऐसी सूरत में जो कि प्राइवेट सेक्टर में नयी फैक्ट्रीज को लाइसेंस दिया गया है जिनको लाइसेंस कमीशन फाइनल नहीं कर रहा है क्या गवर्नमेंट इस मसले को हल करने के लिए कोई कदम लेने जाती है और उनको लाइसेंस करने वाली है ?

Shri Annasahib Shinde I am aware that there has been some difficulty experienced by the existing licensed sugar factories in regard to their long-term plans The Government is also seized of the problem and in the near future we expect that this problem will be looked into symapthetically

Food Production

\+

*1355 **Shri R Barua:**
Shri D N Patodia

Will the Minister of **Food and Agriculture** be pleased to state

(a) whether the *per capita* **availability of foodgrains now is more than**